देने के बजाय स्वदेशी कंपनियों को ऊपर उठाया जाएगा और यह गांरटी दी जाएगी कि विदेशी कपंनियों को नहीं देंगे, सिर्फ हिन्दुसतानी कंपनियों को देंगे?

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: سر، میرا 'بی" پارٹ یہ ہے کہ جوترمیم لانے جارہے ہیں، اس کا نوٹ ہی بہت خطرناک ہے- یہ اختیار امریکن کمپینی کے لئے راستہ صاف کرتا ہے- توکیا اس نوٹ کوہٹا کر ودیشی کمپنیوں کوروزگار دینے کے بجائے سودیشی کمپنیوں کواوپر اٹھایا جائے گا اوریہ گارنٹی دی جائے گی کہ ودیشی کمپنیوں کونہیں دینگے، صرف ہندوستانی کمپنیوں کوہی دیں گے؟

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :सभापति जी, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं कि हमको स्वदेशी लोगों की कंपनियों की टेक्नोलोजी को ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय और केन्द्र का काम नार्मस ले-डाऊन करना है, किसी कंपनी को काम देना नहीं है। यह पूरा का पूरा अधिकार प्रदेश सरकारों का है। हम लोगों ने नोटिफिकेशन में कुछ शर्ते लगाई है।

Cancellation of Passports in UP

*403. SHRI ABU ASIM AZMI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a large number of persons belonging to the minority communities from UP in general and from Azamgarh District in particular have been served with show cause notices about the cancellation of their passports by the Passport Office at Lucknow;

(b) if so, the number of persons who have been issued such notices along with the details of the allegation against each; and

(c) the number of passports which have been cancelled during the last six months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI VINOD KHANNA): (a) and (b) No, Sir. Show cause notices were issued to all those passport holders whose passports were issued by Regional Passport Office (RPO) LUCKNOW on overdue basis pending paolice verification reports and subsequently adverse/incomplete police verification reports were receive. RPO LUCKNOW had served these notices to all concerned passport holders of its jurisdiction in UTTAR PRADESH irrespective of region

or community. Out of a total of 20,076 notices issued, 1313 pertain to district AZAMGARH.

(c) Total number of passports surrendered against notices issued between October, 2002 and January, 2003, as on 31-3-2003 are 1573 out of which 1165 cases have been referred to police authorities for fresh reports.

श्री अबू आसिम आजमी :सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, उन्होंने कष्ट उठाया, परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर अधूरा है। मैंने जो पूछा था, मुझे उसका पता नहीं चल सका।

श्री सभापति :एक धन्यवाद और दे दीजिए, अब की बार पूरा उत्तर आ जाएगा।

श्री अबू आसिम आजमी :पुलिस ने जो ऐलिगेशन लगाया उन पासपोर्ट होल्डर्स के ऊपर, इसकी कापी मुझे नहीं दी गई। क्या सरकार पास पोर्ट के लिए पुलिस और एलआईयू के जरिए रिपोर्ट भेजने के नाम पर फैले हुए भ्रष्टाचार से वाकिफ है? पुलिस और एलाआईयू 500 रूपए से 1500 रूपये तक मांगती है और जो लोग इन्हें रिश्वत नहीं देते उनके खिलाफ ऐडवर्स रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है। अगर ऐसा है तो सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए **क्या** स्टेप लिए है ताकि उनको पास पोर्ट आसानी से मिल सके?

SHRI VINOD KHANNA: Mr. Chairman, Sir, there is a certain procedure which has been laid down, right from the submission of applications to the approving of passports.

श्री अबू आसिम आजमी : सर, मैं उत्तर हिन्दी में सुनना चाहता हूं। अभी हिन्दी के बारे में बात हुई है और हिन्दी को सरकार बढ़ाना चाहती है मगर हिन्दी में जवाब नहीं दे सकती।

श्री विनोद खन्ना :मैं दोनो भाषाओं में बोलने की कोशिश करूंगा। सभापति जी, पासपोर्ट आफिस का पूरा प्रयास होता है कि सभी **लोगों** को पासपोर्ट ज्ल्दी से जल्दी दिया जाए इसलिए

We have made a provision that a person will receive a passport within 35 days, Sir. earlier, the passports were issued without police verification report. Now, taking into account the national security implications, since 2000, we have decided that we will not issue any passports till such time the police verification reports are received, and even if we are giving passports on *tatkaal* basis, they

are only issued, if there is a character verifcation certificate, issued by an officer of the rank of a Deputy Secretary and above. In that case, a passport is issued for one year, and also for five years. But after one year, if there is an advers police report, the passport is again called back and its has to be surrendered for re-verification.

So far as the question of bribery is concerned, Sir, we all know that this thing has been going on for a long time. We are taking utmost precaution in this respect. Various issues are involved in this and all are being addressed.

श्री अबू आसिम आजमी :सभापति जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत सारे लोगों को पहले पासपोर्ट मिल गया था, कई साल पहले मिल गया था और उन्होने बड़ी मुश्किल से भागदौड़ करके विदेश जाने के लिए नौकरी का वीजा लगाया। वीजा लगाने के बाद उन्होने वहां विदेश में नौकरी की ओर विदेश से वापिस आने के बाद हालांकि उनके पास पोर्ट पर वीजा लगा हुआ है लेकिन ऐसे पासपोर्ट को डिटेन कर लिया गया है और उनसे पाचं-पाचं हजार रूपए तक मांगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पैसा देने को भी तैयार है लेकिन जाति के नाम पर, साम्प्रदायिकता के नाम पर उन लोगो का पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। मेरे पास ऐसे प्रूफ मौजूद हैं।

श्री सभापति :यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप मंत्री जी को वह प्रूफ दे दें, उन पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी।

श्री अबू आसिम आजमी : मैं मंत्री जी से यह आश्वसन चाहता हूं कि वे लोग जो अपने घरों की रोजी-रोटी चलाते हैं...(**व्यवधान**)....

SHRI VINOD KHANNA: Sir, if the hon. Member sends the details to me, I will take action. *(Interruptions)*

श्री सभापति :ठीक है, अब आप बैठ जाइए।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, हमारा सवाल पूरा होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह चुके है ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आपका क्वेश्चन हो गया है, आप जो शिकयतें हैं वह उनके पास भेज दीजिए, अच्छा एक्शन होगा।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें नौकरी यहां नहीं मिल रही है।

श्री सभापति : यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। बैठ जाइए। श्री अमर सिंह।

श्री अबू आसिम आजमी :उनको नौकरी मिली हुई है लेकिन उनका पासपोर्ट ले लिया गया है। उनको पास पोर्ट मिलना चाहिए।

श्री सभापति : श्री अमर सिंह जी।

श्री अबू आसिम आजमी : इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है। ...(**व्यवधान**)..

श्री सभापति : मैं एलाऊ नहीं करूंगा , It will not go on record,श्री अमर सिंह जी, आप बोलिए।

श्री अबू आसिम आजमी :*

श्री अमर सिंह :सभापति महोदया,अभी हमारे काबिल दोस्त विनोद खन्ना जी ने बताया कि पासपोर्ट इश्यू करने की कुछ पद्धति होती है, कुछ कार्य-प्रणाली होती है लेकिन यह प्रश्न हमारे जनपद आजमगढ़ से संबंधित है। मैं बहुत विनय से आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि एक संप्रदाय के लोगो का ही पासपोर्ट रोका जा रहा है ? अगर ऐसा है तो उस सम्प्रदाय में असुरक्षा की भावना नहीं फैलेगी? अगर आपको जानकारी है तो आप बताएं कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों की इंक्वायरी क्यों हो रही है? एक ही समुदाय के लोगों को दोषी क्यों पाया जा रहा है? कृपया इस विषय में आप सदन को जानकारी देने की कृपा करें।

SHRI VINOD KHANNA: Hon. Chairman, Sir, I think the hon. Member is misinformed. There is a system. When anybody applies for a passport, nobody is asked about the religion or region or community or any such thing. Everything is fed into the computer. So, the computer generates the show cause notices. This is only on the basis of the people who have incomplete or adverse police verification record. The computer generates the show cause notices. Nobody manually does this. So, the computer does this. The show cause notices are generated by the computer, it is not done manually. And, show cause notices have been issued to various people from all walks of life, from various communities who have incomplete or adverse police verification records. So, I think, this is a baseless allegation.

---

*Not recorded.

SHRI AMAR SINGH: There should be a summary disposal of the cases. Why only their cases are pending? Is it only the computer that only a particular community cases will not be disposed of?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति महोदय, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं क्योकि एक विशेष समुदाय का प्रश्न यहां उठाया गया है। अभी हमारे सहयोगी मंत्री ने कहा कि हम वह सवाल पूछते ही नहीं हैं, वह सवाल फार्म में ही नहीं है। जब वह सवाल उस फार्म में ही नहीं है तो किस आधार पर हम कह सकते है कि एक विशेष समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है?दूसरी बात जो इन्होने कही, उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम्प्यूंटर में इस प्रकार का कोई प्रोग्रम नहीं है कि किसी खास नाम वालों के साथ ऐसा किया जाए। करीब 20,000 लोगों को ये नोटिस इश्यू किए गए हैं। वर्ष 1994-99 के बीच में जितने पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बिना इश्यू हुए थे, उनके बारे में ये नोटिस इश्यू किए गए है। यह सवाल सिर्फ आजमगढ़ का नहीं है, उत्तर प्रदेश लखनऊ आर.पी.ओ. के जितने जिले हैं, सबके बारे मे यह सवाल है।

† मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : हजारीबाग के बारे में भी हैं?

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: ہزاریباغ کے بارے میں بھی ہے؟

श्री यशवंत सिन्हा: हजारीबाग शायद रांची आर.पी.ओ. में होगा। आप शायद उसी में हैं। मैं यह कह रहा था कि अगर इस प्रकार की भांति है तो कृपया उसे मन से निकाल दीजिए। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं।

श्री अमर सिंह: हमने वह भ्रांति निकाल दी लेकिन आप जरा जल्दी से पक्ष में या विपक्ष में इन केसेज का निस्तारण करवा दीजिए।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, usually people have to wait for a long time to get their passport. Hon. Minister has said that the time period is fixed for 35 days after police verification. I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal from the Government to open new passport offices to meet the demand of the people seeking passports.

SHRI VINOD KHANNA: Sir, the latest initiative of the Government is that we would receive applications at the district level and theb they would be sent to the Regional Passport Offices, which will help the people. They will allow the people to submit the application at the district headquarters and then the police verification will be done. All those papers will be completed and sent to the

† Transliteration of Urdu speech.

Regional Passport Offices. I think, this is a big step that we have taken and it will really enable the people to get passports quicker.

MR. CHAIRMAN: Question no. 404, Shri Krishnamurthy.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Sir, I am authorised to put the supplementary.

श्री सभापति :आपका बाद में आएगा।

*404. *[The questioner (Shri K.B. Krishna Murthy) was absent for answer vide pages 61-62.]*

*405. *[The questioner (Shri Lalit Suri) was absent for answer vide page 62-63.]*

Outsourcing of Business services

*406. SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether some States of the USA have passed legislation againt the outsourcing of business services like call centres in a move to provide employment to locals;

(b) to what extent this would affect the operations of call centres running in India with clientele comprising of major US MNCs;

(c) whether NASSCOM has initiated any damage control measures by sending a delegation to US to lobby for a *status quo* on this issue; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Rajya Sabha.

Statement

(a) and (b) No laws have been passed so far. However, Bills were introduced in the New Jersey State's Senate and Assembly which required every State contract for the performance of services, to include provisions specifying that only persons authorized to work in the United States may be employed under the contract or any subcontract. As per current status, after having been passed by the